प्रेस वार्ता -प्रारंभिक उदबोधन – वीर बालक दिवस

- सबसे पहले मैं इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित आप सभी सम्मानित इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों का विभाग की ओर से स्वागत करती हूँ। आप सभी लोकतंत्र के सशक्त स्तंभ हैं। आपके माध्यम से सरकार की योजनाएँ, नीतियाँ और जनकल्याणकारी प्रयास समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचते हैं।
- आज 26 दिसम्बर है और हर साल हम इस दिन वीर बाल दिवस के रूप में मनाते है। आज मैं अपनी प्रेस वार्ता में सबसे पहले 'वीर बाल दिवस' के अवसर पर महान गुरु गोबिंद सिंह जी के दो सबसे छोटे साहिबजादों, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन करती हूँ।
- दोनो वीर बालकों ने अपने धर्म और सिद्धांतों की रक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया और शहादत का रास्ता चुना। आज ही के दिन 26 दिसंबर 1705 को दोनों साहबज़ादों को आक्रांताओं ने ज़िंदा दीवार में चुनवा दिया था। इस समय इनकी उम्र मात्र 9 साल और 6 साल की थी। इतनी कम उम्र में दोनों साहिबज़ादों ने शहादत स्वीकार कर युवा पीढी को साहस और निष्ठा के मायने समझा दिये।
- इतिहास का यह अभूतपूर्व बलिदान नई पीढी के लिये प्रेरणा बने इसके लिये हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 9 जनवरी, 2022 को गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर 26 दिसम्बर को 'वीर बाल दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की थी।
- यह दिन केवल सिख समुदाय के लिए नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का दिन है
- हमारे विभाग के साथ साथ देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी बच्चों को संबोधित करते हैं। मैं एक बार पुनः दोनों साहिबजादों के बलिदान को नमन करती हूँ।

प्रेस वार्ता - दिनांक 26 दिसम्बर 2025

- एक बार पुन: आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद भी देती हूँ कि समय-समय पर आपके द्वारा ऐसे अनेक मुददों से मुझे अवगत कराया जाता है जिसमें सुधार अपेक्षित रहता है। मेरा भी प्रयास रहता है कि उन मुददों पर प्रभावी कार्यवाही हो। वास्तव में व्यवस्थाओं में तेजी से सुधार इसी प्रक्रिया से संभव हो पाता है।
- भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र भाई मोदी और माननीय मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने पिछले दो वर्षों में विकास के हर क्षेत्र में, विशेषकर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।
- माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में विकास की गति तेज हुई है और विकास के संकेतकों में भी सकारात्मक सुधार हुआ है। प्रदेश में परिवर्तन का नया दौर शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और विकसित भारत 2047 में मध्यप्रदेश अहम भूमिका निभा रहा है।
- आज मैं, मेरे विभाग - महिला एवं बाल विकास द्वारा पिछले 2 वर्षों में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों, उपलब्धियों और आगामी प्राथमिकताओं को आपसे साझा कर रही हूँ।
- हमारी सरकार का मेरे विभाग को लेकर स्पष्ट दृष्टिकोण है - महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा, बाल संरक्षण और सुदृढ पोषण।
- इसी के अनुरूप महिला एवं बाल विकास विभाग ने अनेक ऐतिहासिक और प्रभावशाली पहलें की हैं। अनेक योजनाओं में और गतिविधियों में हम देश में अग्रणी स्थान पर हैं।

महिला सशक्तिकरण

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-

- **सबसे पहले मैं महिलाओं के सशक्तिकरण से सम्बंधित योजनाओं पर प्रकाश डालना चाहूँगी।**
- **सर्वाधिक लोकप्रिय योजना मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का उल्लेख करना चाहूँगी। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुई है। यह उल्लेखनीय है कि इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित राशि अंतरण की प्रशंसा देशभर में हो रही है और अनेक राज्यों ने मध्यप्रदेश के इस मॉडल को अपनाया है।**
- **जून 2023 से दिसम्बर 2025 तक योजना अंतर्गत 31 किस्तों का नियमित भुगतान किया गया है।**
- **वर्तमान में लगभग 1 करोड़ 26 लाख 87 हजार से अधिक महिलाएँ इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं, जिन्हें अब तक रूपये 48,632 करोड़ से अधिक की राशि सीधे खातों में अंतरित की जा चुकी है।**
- ***विगत दो वर्षों में लगभग रूपये 38,635 करोड़ राशि अंतरित की गई है।***
- **यह योजना महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य-पोषण में सुधार तथा पारिवारिक निर्णयों में उनकी भागीदारी को सशक्त बना रही है।**
- **आगामी 3 वर्षों में महिलाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की दिशा में कार्य किया जायेगा।**

मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना -

- हमारी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाने के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना में अब तक 52 लाख से अधिक बालिकाओं का पंजीयन किया जा चुका है।
- विगत दो वर्षों में 6.40 लाख बालिकाओं को ₹ 350 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।
- आगामी तीन वर्षों में हमारा लक्ष्य 8 लाख नए पंजीयन करना एवं 25 लाख से अधिक बालिकाओं को छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन राशि का भुगतान सुनिश्चित करना है।
- मुझे खुशी है कि आगामी 3 वर्ष के भीतर अर्थात अप्रैल 2027 से ही हमारी बालिकाओं का पहला बैच 21 वर्ष की आयु पूर्ण करेगा । हम उन्हें एक लाख रूपये की परिपक्वता राशि का भुगतान करेंगे।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ -

- प्रधानमंत्री जी ने बालिकाओं की शिक्षा और समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक बदलाव के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की जो हमारे प्रदेश में भी प्रभावी रूप से संचालित की जा रही है।
- इस योजना का उददेश्य बेटियों के प्रति समाज में सकारात्मक बदलाव और उनके सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर जन सामान्य को जागरूक करना है इस परिपेक्ष्य में पूरे प्रदेश में अनेकों गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।
- इस योजना में महिलाओं/बालिकाओं के लिये पिंक ड्राइविंग लाइसेंस गतिविधि के तहत 6,134 महिलाओं/बालिकाओं को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किये गए हैं।
- हमनें समाज की ही सफल बालिकाओं/महिलाओं को 1,794 जेंडर चैंपियंस बनाया है जो न केवल अन्य बालिकाओं के लिये प्रेरणा है बल्कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के सन्देश देकर भी लोगों को जागरूक कर रही हैं।
- सशक्त वाहिनी कार्यक्रम के तहत बेटियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नि:शुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। विगत वर्षों में 7 हजार से अधिक बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया गया है ।
- आगामी 3 वर्षों में शाला त्यागी बालिकाओं को मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10वीं व 12वीं की परीक्षा दिलाकर उनकी स्कूल शिक्षा पूर्ण कराने पर कार्य किया जायेगा । साथ ही शाला त्यागी बालिकाएं जो कि आगे पढ़ने की इच्छुक नहीं हैं उन्हे कौशल प्रशिक्षण प्रदाय करने की योजना है ।

वन स्टॉप सेंटर -

- घरेलू अथवा किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिये वन स्टॉप सेंटर आज सबसे बडी सुविधा के रूप में पहचान बना चुका है जहॉ एक ही छत के नीचे पीडित महिला को स्वास्थ्य, चिकित्सा, परामर्श, विधिक सहायता एवं पुलिस सहायता प्रदान की जा रही है। प्रदेश में 57 वन स्टॉप सेंटर संचालित किए जा रहे हैं।
- मैं बताना चाहूँगी कि पिछले 2 वर्षों में हमने 5 नये वन स्टॉप सेंटर भी प्रारंभ किये हैं जिसमें महिलाओं को एक ही स्थान पर सहायता प्रदान करने की सुविधा का विस्तार हुआ है।
- विगत 02 वर्ष में 54,627 संकटग्रस्त महिलाओं को आवश्यक सुविधा एवं सहायता उपलब्ध कराई गई है। ऐसी कोई भी महिला जो संकटग्रस्त है उसे विभाग में न केवल सहायता की है वरन उसे सम्बल भी दिया है। इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये प्रभावी परामर्श भी दिया जा रहा है।
- इस सुविधा को और विस्तारित करते हुये आगामी 3 वर्षों में 08 नवीन वन स्टॉप सेंटर प्रारंभ किये जाने का हमारा लक्ष्य है।

महिला हेल्पलाइन 181-

- किसी भी तरह के संकट में आई महिलाओं की त्वरित सहायता के लिए नि:शुल्क महिला हेल्पलाइन 181 संचालित की जा रही है। यह हेल्पलाइन 24 घंटे, 7 दिन संचालित है।
- विगत 02 वर्ष में लगभग 2,36,723 महिलाओं द्वारा इस सुविधा का लाभ प्राप्त किया गया है।
- महिला हेल्पलाइन को पुलिस हेल्पडेस्क, चाईल्ड हेल्प लाइन एवं वन स्टॉप सेंटर से इंटीग्रेट किया गया है।

वर्किंग वूमेन हॉस्टल -

- कामकाजी महिलाएं जब अपने घर से बाहर नौकरी करने के लिए जाती हैं तब उनके सामने यह समस्या रहती है कि वह कहां रहे। ऐसी जगह जहां उन्हें सुरक्षित महसूस हो।
- हमारी सरकार द्वारा इसी विचार को लेकर प्रदेश में सखी निवास (वर्किंग वूमन हॉस्टल) बनाए जा रहे हैं।
- वर्तमान में भोपाल में 1 और इन्दौर में 2, कुल 03 शासकीय सखी निवास संचालित है।
- मैंने महसूस किया कि प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के लिये सुरक्षित आवास की अधिक आवश्यकता है मुझे यह बताते हुये खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से प्रदेश में पहली बार राशि रूपये 284 करोड़ की लागत से 5121 सीट क्षमता के 08 नवीन वर्किंग वुमन हॉस्टल उज्जैन, धार, भिंड, रायसेन सिंगरौली, देवास, नर्मदापुरम झाबुआ में निर्मित किये जायेंगे ।
- इससे कामकाजी महिलाओं हेतु सुरक्षित व सुविधापूर्ण आवास उपलब्ध होगा। यह समस्त भवन आगामी 3 वर्षों में पूर्ण रूप से संचालित कर दिये जायेंगे । यह प्रदेश की कामकाजी बहनों को मोहन सरकार की ओर से बडी सौगात होगी ।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना -

- **मैं बताना चाहूँगी कि प्रारंभ से ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में हम देश में पहला स्थान प्राप्त कर रहे हैं।**
- **जैसा कि आपको ज्ञात है कि योजना में गरीब गर्भवती माताओं को स्वयं की देखभाल और पोषण के लिये प्रथम संतान पर रूपये 5000 एवं द्वितीय संतान पर बालिका होने पर रूपये 6000 की प्रसूति सहायता प्रदान की जाती है।**
- **योजना अंतर्गत विगत दो वर्षों में लगभग 10.5 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं का पंजीयन कर राशि रुपये 547 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है।**
- **हमारा लक्ष्य है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस योजना के तहत आगामी 3 वर्षों में 21 लाख नवीन पंजीयन करेंगे।**

हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमन

- प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की गतिविधियों को विस्तार देने हेतु हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमन का संचालन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से महिलाओं को एक ही स्थान पर सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
- हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमन अंतर्गत 100 दिवसीय विशेष जागरुकता अभियान में जिला, परियोजना व ग्राम स्तर पर कुल 1,47,089 जागरूकता गतिविधि आयोजित की गयी।
- हम होंगे कामयाब अभियान अंतर्गत जेंडर उन्मुखीकरण के सत्र आयोजित कर 2.58 लाख प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया।
- महिलाओं के लिए कानूनी सहायता,परामर्श और जागरूकता हेतु 596 शिविर आयोजित किए गए जिसमें 35,771 महिलाएं सम्मिलित हुईं।
- शिक्षा विभाग एवं उद्यमिता कौशल विकास विभाग के सहयोग से 48,546 बालिकाओं एवं महिलाओं को डिजिटल साक्षरता, बुनियादी कंप्यूटर जानकारी दी गई।

बाल विवाह -

- आप सभी जानते हैं बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति ही नहीं, बल्कि कानूनी अपराध भी है। बाल विवाह से न केवल बच्चे का स्वास्थ्य प्रभावित होता है बल्कि उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास में भी बाधा उत्पन्न होती है ।
- कम उम्र में विवाह से न केवल माता कमजोर होती है वरन बच्चा भी कुपोषित होने की संभावना रहती है, इस प्रकार का दुष्चक्र चलता रहता है जिससे निरंतर भावी पीढी प्रभावित होती रहती है । यह दुष्चक्र सभी के समन्वित प्रयास से ही तोडा जा सकता है और मुझे खुशी है कि समन्वित प्रयासों से प्रदेश में बाल विवाह के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। नेशनल फेमिलि हेल्थ सर्वे - 4 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में बाल विवाह का प्रतिशत 32.4 था जो नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे-5 में घटकर 23.1 प्रतिशत रह गया है।
- महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों, स्वयंसेवी संगठनों, जन प्रतिनिधियों, सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर निरंतर जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।
- हम प्रदेश को बाल विवाह मुक्त करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं लेकिन इसके लिये समाजिक जागरूकता एवं सहयोग अत्यंत आवश्यक है । अत: मेरा मीडिया से अनुरोध है कि वे भी हमारे बाल विवाह मुक्त मध्यप्रदेश अभियान में सहभागी बने। बाल विवाह के दुष्परिणामों से समाज को जागरूक करने में सहयोग करें।

नारी सशक्तिकरण मिशन -

- **Women Led Development (महिला नेतृत्व विकास) को केंद्रित करते हुए प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण हेतु नारी सशक्तिकरण मिशन लागू है जिसका उद्देश्य महिलाओं की विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी तथा संसाधनों और अधिकारों तक उनकी पहुँच को सुनिश्चित करना है।**
- **मिशन के प्रमुख 5 घटक स्वास्थ्य व पोषण, शिक्षा और जीवन कौशल, आर्थिक स्वावलम्बन, सुरक्षा और संरक्षण, संवाद से व्यवहार परिवर्तन है। माननीय मंत्री महिला बाल विकास की अध्यक्षता में मिशन की अनुश्रवन समिति की बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें मिशन के सभी सहयोगी विभागों के द्वारा मिशन कार्ययोजना बनाई गई है।**

बाल संरक्षण -

- महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ बाल संरक्षण भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। 18 वर्ष से कम उम्र का प्रत्येक बालक या बालिका जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है और उनके पालक इस हेतु सक्षम नहीं है अथवा वे अनाथ हैं ऐसे समस्त बच्चों का सम्पूर्ण संरक्षण भारत सरकार की सहायता से मिशन वात्सल्य अंतर्गत किया जाता है।
- बाल संरक्षण के लिए मिशन वात्सल्य अंतर्गत अनेक योजनाओं और बाल देखरेख संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है।
- प्रदेश में 35 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण, 67 बालगृह, 14 खुला आश्रय गृह, 18 सम्प्रेक्षण गृह, 03 विशेष गृह संचालित हैं। इन गृहों में देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद एवं विधि विवादित 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे निवासरत हैं।
- मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत एवं निर्मुक्त होने वाले देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से वित्तीय साक्षरता, आर्थिक स्वावलंबन, साइबर सुरक्षा, लैंगिक समानता, बाल शोषण से संबंधित जागरूकता जैसे विषयों में लगभग 1270 बच्चों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- इन बच्चों को आईटीआई के विभिन्न ट्रेड्स तथा बेकिंग एवं कुकिंग के अतिरिक्त हाउसकीपिंग, हॉर्स राइडिंग, फ्रंट ऑफिस आदि विषयों में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि, वे अपने पैरों पर खडे हो सके।
- मुझे बताते हुये हर्ष है कि विगत 2 वर्षों में हमने 132 बच्चों को संस्थाओं से निकलने के बाद विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें से 56 बच्चों को रोजगार भी प्राप्त हो गया है।

स्पॉन्सरशिप योजना-

- अनाथ एवं अन्य देखरेख एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना के तहत रुपये 4,000 प्रति माह प्रदान कर परिवार में ही बच्चों की देखरेख की जा रही है।
- वर्ष 2024-2025 में 20,243 बच्चों को स्पांसरशिप से लाभान्वित किया गया है मैं बताना चाहूँगी कि इस योजना में हम देश में दूसरे स्थान पर हैं।
- वर्ष 2025-2026 में 32,896 बच्चों को स्पांसरशिप से लाभान्वित किया जायेगा। आगामी 3 वर्षों में इस श्रेणी के सभी बच्चों को लाभांवित करने का हमारा प्रयास रहेगा।
- इंदौर, भोपाल एवं कटनी के बाल गृहों के बच्चों के लिए - STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) Lab की स्थापना की गई जिससे कि वह आधुनिक तकनीकी एवं विज्ञान से अधिक जुडाव महसूस करें।

कोविड काल में प्रभावित बच्चों के लिये विशेष योजना -

- जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड में अनेक लोग प्रभावित हुये हैं इनमें दुर्भाग्य से ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। प्रदेश सरकार ने ऐसे बच्चों के लिये देश की पहली मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना बनाई। इसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड के सामने अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर योजना लागू की।
- मैं बताना चाहूंगी कि कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना के अंतर्गत 1,014 बच्चों को रुपये 5,000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता, नि:शुल्क खाद्यान्न सुरक्षा एवं शिक्षा सहायता प्रदान की जा रही है।
- पीएम केयर योजना के तहत 432 बच्चों से भी संवाद स्थापित कर देखरेख, संरक्षण, स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- बाल देखरेख संस्थाओं से 18 वर्ष पूर्ण कर चुके बच्चों के लिये कोई योजना नहीं थी पर प्रदेश सरकार ने देश में अपनी तरह की अभिनव योजना मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू की है जिसके माध्यम से बाल देखरेख संस्थाओं से मुक्त होने वाले सभी 18 वर्ष से अधिक आयु के अनाथ एवं देखभाल की आवश्यकता वाले युवाओं को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग देकर समाज की मुख्यधारा में पुनर्स्थापित किया जा रहा है।

- इस योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चों को रुपये 4000 प्रति माह तथा संस्थाओं से निकलने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को रुपये 5000 प्रति माह की सहायता प्रदान की जाती है।
- माननीय मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी की मंशा थी कि देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के वैयक्तिक विकास हेतु उन्हें भी समाज की मुख्यधारा में लाने के लिये उनके मध्य खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित किया जाये।
- विभाग ने मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुरूप प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री खेल एवं सांस्कृतिक महोत्सवों का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश के बाल गृहों के 860 बच्चों ने भाग लिया। इन बच्चों के चेहरों पर अदभुत प्रसन्नता और उत्साह दिखा।
- मुझे बताते हुये प्रसन्नता है कि बाल संप्रेक्षण गृह भोपाल के बच्चों को इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के सहयोग से शतरंज में प्रशिक्षित किया और उसके परिणाम स्वरूप फिडे एवं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन द्वारा आयोजित चेस चैंपियनशिप में 50 देशों के जूवेनाईल होम के बच्चों ने सहभागिता की और 2023-24 और 2024-25 में दोनो सालों में लगातार भोपाल के बच्चों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया।
- ऐयिशाई इंटरकोंटिनेंटल चैम्पियनशिप में भी भोपाल की बालिकाओं ने गोल्ड मेंडल प्राप्त किया। यह प्रदेश के लिये गौरव का विषय है।

बाल विकास एवं पोषण

- बच्चों, बालिकाओं और महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए विभाग विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- वर्तमान में प्रदेश में 97हजार 882 आंगनवाडी केन्द्र संचालित हैं इन केन्द्रों में 0 से 6 वर्ष के 58 लाख से ज्यादा बच्चों, 7.5 लाख से ज्यादा गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं तथा 1 लाख से ज्यादा किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शालापूर्व शिक्षा प्रदान की जा रही है।
- हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी ने इस सम्बंध में कभी भी बजट की कमी नहीं होने दी। इसका उदाहरण है कि प्रदेश में एक साथ 12670 मिनी आंगनवाडी केन्द्रों को मुख्य आंगनवाडी केन्द्रों में परिवर्तित कर दिया। एक ही बार में इतनी सारी आंगनवाडियों को अपग्रेड करना एक उल्लेखनीय कदम है। इससे इन केन्द्रों में बाल विकास सेवाओं का पूर्ण विस्तार हुआ है एवं 12670 नवीन रोजगार सृजित हुए हैं।
- 12670 मिनी आंगनवाडी केन्द्रों को मुख्य आंगनवाडी केन्द्रों में परिवर्तन से पर्यवेक्षक के 476 पद सृजित हुए हैं जिन पर भर्ती की कार्यवाही की जा रही है।
- मध्यप्रदेश ने देश में पहली बार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकओं की भर्ती हेतु ऑनलाइन, पारदर्शी और मेरिट-आधारित चयन प्रक्रिया लागू कर एक नई मिसाल स्थापित की है। इस प्रक्रिया को भारत सरकार द्वारा भी सराहा गया है।
- इस प्रक्रिया के तहत अब तक 1 हजार 510 आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं 13 हजार 132 सहायिका का चयन कर नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि इस पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से चयन उपरांत शिकायतों / दावों की संख्या नगण्य रही है।
- पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम अंतर्गत पोषण के साथ साथ बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए 91429 आंगनवाडी कार्यकर्ताओं का आधारशिला एवं नवचेतना फ्रेमवर्क से क्षमता संवर्धन किया गया है।

- **यह बहुत ही उल्लेखनीय है कि हमारी 98753 आंगनवाडी कार्यकर्ताओं में से 31 प्रतिशत कार्यकर्ता स्नातक या स्नाकोत्तर हैं 39 प्रतिशत कार्यकर्ता दसवी या बारहवी योग्यता धारी हैं इससे आंगनवाडी सेवा की गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार हुआ है।**
- **आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को जीवन सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोडा गया है। बीमा के प्रीमीयम की राशि सरकार द्वारा वहन की जा रही है। वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत 70932 एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत 92118 कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को प्रीमियम राशि दी गई है।**
- **आंगनवाडी केन्द्रों में आने वाले बच्चों एवं उनके परिवार के लोगों के आधार कार्ड निर्माण हेतु बनाये जाने हेतु हमारे आयुक्त पंजीयक के रूप में कार्य कर रहे हैं।**

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

- **विशेष जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में निवास करने वाले बच्चों और महिलाओं को सुगमतापूर्वक पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उदेश्य से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) अंतर्गत 681 नवीन आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन प्रारंभ किया गया है।**
- **पी एम जनमन के तहत भारत सरकार द्वारा 704 आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु भवन स्वीकृत किए गए हैं इस योजना में 147 भवन पूर्ण कर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है.**
- **इसके साथ ही धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में भी 66 नवीन आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन प्रारंभ किया गया है।**
- **प्रदेश सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रो के सुदृढ़ीकरण हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाते हुये राज्य मद से भवन निर्माण हेतु प्रति भवन निर्धारित राशि 11.22 लाख का व्यय भार शत प्रतिशत किया जा रहा है।**
- **पिछले 02 वर्षों में 4097 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की राशि जारी की गई है।**
- **बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वच्छ तथा अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने हेतु आगामी 3 वर्षों में 9000 आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण का हम राज्य मद से करेंगे।**
- **प्रदेश के 24662 आंगनवाड़ी केन्द्रो का उन्नयन सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्र के रूप में किया जा रहा है, इन केन्द्रों में स्मार्ट क्लास रूम और पोषण वाटिका के रूप में विकसित किया जा रहा है। ताकि बच्चों की शिक्षा एवं पोषण पर सकारात्मक प्रभाव पडे।**

डिजिटल इंडिया अंतर्गत विशेष नवाचार

- हम माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल तकनीक के माध्यम से भी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर रहे हैं।
- विभाग द्वारा विकसित सम्पर्क ऐप के माध्यम से आंगनवाडी केन्द्र के सभी संसाधनों को ऑनलाईन ऐसेट डायरी मॉड्यूल में दर्ज किया गया जो देश में आंगनवाडी सेवाओं के तहत किया गया अपने तरह का अभिनव प्रयास है।
- आंगनवाडी सेवाओं का सुदृढीकरण करते हुए विभाग द्वारा आंगनवाडी कार्यकताओं की जीपीएस आधारित उपस्थिति सुनिश्चित की गयी है इस रियल टाईम मॉनिटरिंग की पूरे देश में सराहना की गई।
- पोषण ट्रैकर एप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म, सेवाओं की निगरानी को और अधिक सशक्त बना रहे हैं।
- मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पोषण ट्रैकर ऐप में FRS - Facial Recognition System (आधार फेस मैचिंग) का अनिवार्य प्रावधान किया गया है। जिसके तहत मध्य प्रदेश में पूरक पोषण आहार हेतु पात्र हितग्राहियों में 99.14% गर्भवती महिलाओं, 98.47% धात्री माताओं तथा 92.12% 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों का FRS पूर्ण कर लिया गया है।

विगत वर्षों में प्रदेश में कुपोषण की स्थिति में हुए सुधार

- हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिये हमेशा इस मुददे को अपनी प्राथमिकता में रखा है। हाल ही में धार जिले में प्रधानमंत्री जी ने 8वे पोषण माह का शुभारंभ किया, जो वास्तव में "सुपोषित मध्यप्रदेश, सशक्त मध्यप्रदेश" के निर्माण का एक संकल्प है।
- कुपोषण केवल मध्यप्रदेश या देश के अन्य राज्यों के लिये ही चुनौती नही है वरन सम्पूर्ण विश्व के देश कही न कही इस चुनौती का सामना कर रहे हैं।
- मैं मध्यप्रदेश के द्वारा विगत वर्षों में किये गये समन्वित प्रयास से प्रदेश के बच्चों के पोषण स्तर में उल्लेखनीय सुधार की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूॅ, मै अभी जो आंकडे पेश कर रही हूॅ वह राष्ट्रीय स्तर से प्रतिष्ठित सर्वे के आंकडे हैं जो स्वत: यह बता रहे है कि मध्यप्रदेश के बच्चों का पोषण स्तर बढा है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (NFHS), भारत सरकार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS) के माध्यम से करवाया जाकर रिपोर्ट जारी की गयी है।

1- यह उल्लेखनीय है कि जहॉ NFHS 4 में जारी आंकडों में कम वजन 42.8 प्रतिशत था जो घटकर NFHS 5 में 33 प्रतिशत रह गया।

2- जहॉ NFHS 4 में जारी आंकडों में ठिगनापन 42 प्रतिशत था जो घटकर NFHS 5 में 35.7 प्रतिशत रह गया।

3- जहॉ NFHS 4 में जारी आंकडों में दुबलापन 25.8 प्रतिशत था जो घटकर NFHS 5 में 19.0 प्रतिशत रह गया।

4- जहॉ NFHS 4 में जारी आंकडों में गंभीर कुपोषण 9.2 प्रतिशत था जो घटकर NFHS 5 में 6.5 प्रतिशत रह गया।

- देश में सबसे तेजी से सुधार की दृष्टि में हम अग्रणी प्रदेश में शामिल हैं।
- मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्द्धन कार्यक्रम अंतर्गत SAM, MAM एवं SUW बच्चों का चिन्हांकन कर उनका उपचार एवं पोषण प्रबंधन NRC एवं समुदाय स्तर पर किया जा रहा है।

- **विकसित मध्यप्रदेश 2047 विजन अनुरूप वर्ष 2029 तक विभाग का लक्ष्य है कि वर्ष 2029 तक बच्चों में दुबलापन का स्तर 10 प्रतिशत तक किया जाए। SAM बच्चों के वर्तमान प्रतिशत में 80 प्रतिशत तक कमी लाना, हमारा लक्ष्य है।**
- **इसके लिए कुपोषण मुक्त आंगनवाड़ी, पंचायत, सेक्टर एवं परियोजना घोषित करने का अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के साथ समन्वय कर आकड़ों का एकीकरण किया जाएगा ताकि बेहतर समन्वित रणनीति तैयार कर सकें।**
- **माननीय मुख्यमंत्री की सुपोषित मध्यप्रदेश की संकल्पना को साकार करने सुपोषित मध्यप्रदेश अभियान चलाकर कुपोषण को न्यूनतम स्तर पर लाने का प्रयास करेंगे।**

कुपोषण मुक्त मध्यप्रदेश अभियान -

- मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के बच्चों, माताओं एवं किशोरियों के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से "कुपोषण मुक्त मध्यप्रदेश अभियान" का शुभारंभ किया है। इस अभियान में समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता से जन–आंदोलन के रूप में संचालित किया जा रहा है।
- अभियान का मुख्य लक्ष्य प्रदेश को चरणबद्ध रूप से SAM (अत्यधिक कुपोषण), MAM (मध्यम कुपोषण) एवं SUW (कम वजन) से मुक्त करना है। इसके अंतर्गत गर्भवती एवं धात्री माताओं, नवजात शिशुओं, बच्चों तथा किशोरियों के लिए जीवन-चक्र दृष्टिकोण अपनाते हुए पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और व्यवहार परिवर्तन पर एक साथ कार्य किया जा रहा है।
- अभियान के माध्यम से गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें समुचित उपचार, अतिरिक्त पोषण एवं सतत निगरानी प्रदान की जा रही है।
- प्रदेश सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि कोई भी बच्चा कुपोषण के कारण अपने शारीरिक एवं बौद्धिक विकास से वंचित न रहे। कुपोषण मुक्त मध्यप्रदेश के माध्यम से हम एक स्वस्थ, सशक्त एवं सक्षम भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

मानव संसाधन की पूर्ति

- हमारी सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक नवीन भर्तियाँ की जाएं ताकि नई पीढ़ी को स्थाई रोजगार मिल सके। इस परिप्रेक्ष्य में विभाग ने 560 पर्यवेक्षक के पदों पर भर्ती की कार्यवाही की है जिनके नियुक्ति आदेश जारी किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सांख्यिकी अन्वेषक के 86 पदों और 17 सहायक संचालकों की भर्ती की गई है।
- मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने विगत 02 वर्षों में 36 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान कर उनके परिवारों को संबल प्रदान किया है।
- आगामी वर्षों में हम इसे और बढ़ाते हुए 114 विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों, 682पर्यवेक्षक एवं 146 सांख्यिकी अन्वेषकों के पदों पर भर्ती की कार्यवाही करेंगे।

आभार -

- प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन के नेतृत्व में महिलाओं एवं बालकों के कल्याण हेतु निरंतर गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जा रहा है। जिसके अभूतपूर्व परिणाम सामने आये हैं आज आप समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को स्वयं देख सकते हैं । प्रदेश में मानव विकास सम्बंधी सूचकांकों में देश के अन्य प्रदेशों की तुलना में सकारात्मक बढोत्तरी हुई है ।
- मुझे आशा है कि भविष्य में हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और अधिक प्रभावी कार्य करेगे।
- मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूॅ कि उन्होने केन्द्रीय योजनाओं में पैसे की कमी नही आने दी ।
- मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की आभारी हूॅ कि उनके कुशल नेतृत्व और मागदर्शन में हम बाल कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर कार्यशील हैं ।
- हम सभी मीडियाजनों के प्रति भी अभारी है कि वे हमें समय-समय पर विभाग से सम्बंधित कई महत्वपूर्ण मुददों और समस्याओं से अवगत भी कराते हैं और सकारात्मक खबरों के माध्यम से विभागीय अमले को प्रोत्साहित भी करते हैं।
- आमजन को विभागीय योजनाओं और उपलब्धियों को जन-जन तक पहुचाने में आप सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है एवं मेरी अपेक्षा है कि भविष्य में भी इस प्रकार का सहयोग बनायें रखेंगे ।